गंगाधर बेहरा और अन्य ।

बनाम

ओड़ीशा राज्य

10 अक्टूबर, 2002

[अरिजीत पसायत और एस. बी. सिन्हा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860; धारा 141,148,149 और 302:

हत्या - गैरकानूनी सभा – दोषसिद्धि – घटक –अभिनिर्धारित -, सभा का कोई सदस्य यदि सभा के उद्देश्य और उसके द्वारा किए जाने वाले गैरकानूनी कृत्यों को समझता है, तो ऐसे सदस्य को गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जाएगा- प्रत्यक्ष रूप से किए गए कार्य को साबित करना आवश्यक नहीं है।

समान उद्देश्य और समान इरादा -के बीच का अंतर-चर्चा की गई।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

इच्छुक गवाहों की गवाही-उस पर निर्भरता-अभिनिर्धारित – संबंध गवाहों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं- न्यायालय को ऐसे मामले मे गवाह की विश्वसनीयता पता लगाने के लिस सावधानीपूर्वक साक्ष्य के विश्लेषण करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

मैक्सिमः

' फ़लसस इन यूनो-फ़लसस इन ओम्निबस '-का अर्थ और प्रयोज्यता।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक और डी. डब्ल्यू. -1 के बीच बाजार में एक शेड के निर्माण के संबंध में झगड़ा हुआ था। अभियुक्तगनों द्वारा, मृतक और अभियोजन साक्षियों को खदेड़ा गया था । अभियुक्तों में से दो (अपीलार्थी सं- 7 & 10) मृतक और अन्य लोगों को घसीटकर ले जया गया था और उन पर हमला किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ये आरोपी फरार हो गए। चश्मदीद गवाहों में से एक पीडब्लू-5 ने प्राथमिकी दर्ज कराई।

विचारण न्यायालय ने 21 अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया और उनमें से 15 को धारा 302

सहपठित धारा 149 और धारा 148 के साथ-साथ धारा 307 सहपठित धारा 149 आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। हालाँकि, इसने शेष अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया। दोषी अभियुक्त्गण ने उच्च न्यायालय में असफल अपील दायर की। अपील पर, इस न्यायालय ने मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण्ण कर इसे निपटानेके लिए। उच्च न्यायालय ने मामले की फिर से सुनवाई की और 10 अभियुक्तों के दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा और शेष अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया गया था कि घटना के मुख्य चश्मदीद गवाह मृतक के रिश्तेदार थे और उसी राजनीतिक दल से संबंधित थे जिससे मृतक संबंधित थे; कि गवाहों ने किसी भी अभियुक्त व्यक्त की निश्चित भूमिका का श्रेय नहीं दिया था और धारा 149 लागू नहीं थी; वह आधार जिसके आधार पर कुछ अभियुक्त बरी किए गए थे इन अभियुक्त अपीलार्थियों पर भी तार्किक रूप से लागू थे; कि अन्य स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों का परिक्षन्न या पूछताछ नहीं की गई थी; और यह कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगति थी।

राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय थे; कि अभियुक्त के झूठे निहितार्थ के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया गया था; कि एक स्वतंत्र गवाह की गैर-जांच ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को कमजोर नहीं किया; कि अपराध करने का सामान्य इरादा स्थापित किया गया था; और कि कुछ अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था,परंतु इससे प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य की संगदिघता प्रगट नहीं किया गया था ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्धारित किया ;--,

निर्धारण 1.1 . संबंध किसी गवाह के गवाही की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। ऐसे मामलों में, न्यायालय को गलत निहितार्थ का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप एक पक्षपाती गवाह है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए कोई पदार्थ नहीं। [191 - ई; 192-सी]

दलीप सिंह और अन्य बनाम . पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1953) एस. सी. 364; गुली चंद और अन्य। वी. राजस्थान राज्य, [1974] 3 एस. सी. सी. 698; वादिवेलु थेवर

वी. मद्रास राज्य, ए. आई. आर. (1957) एस. सी. 614; मसाला और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी (1965) एससी 202; पंजाब राज्य बनाम। जागीर सिंह, आकाशवाणी (1973) एससी 2407 और लेहना बनाम। हरियाणा राज्य, [2002] 3 एस. सी. सी. 76, पर निर्भर था।

1.2 . संक्षेप में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए प्रार्थना कुछ गवाहों को पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" (एक चीज में गलत, हर चीज में गलत) का सिद्धांत। यह दलील स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। भले ही इसका बड़ा हिस्सा साक्ष्य की कमी पाई जाती है, यदि अवशेष अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है एक अभियुक्त के, कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने के बावजूद, उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। विशेष भौतिक गवाह या विशेष सामग्री की असत्यता इसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं करेगी। इस उक्ति का भारत में कोई उपयोग नहीं है और गवाह को झूठा नहीं माना जा सकता है। यह केवल सावधानी का नियम है। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे एक न्यायालय परिस्थितियों के एक दिए गए समूह में लागू कर सकता है, लेकिन यह साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम नहीं है| [193 - बी-सी-डी-ई]

निसार अली बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1957) एस. सी. 366, पर निर्भर था।

1.3 . सिद्धांत 'फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस' भारत मे एक खतरनाक और

बिल्कुल नया, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को पूरी तरह से संदर्भ से अलग करके मामले का पुनर्निर्माण करना होगा और जिस पृष्ठभूमि के खिलाफ वे बनाए गए हैं, एकमात्र उपलब्ध तरीका यह है कि साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। [193 - एफ-जी-एच; 194-ए-बी-सी।]

सोहराब एस/ओ बेली नायता और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1972} 2 एस. सी. सी. 751; उगार अहिर और अन्य बनाम बिहार राज्य, आकाशवाणी (1965) एससी 277;

ज़िंगली एरियल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 15 और बालक सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1975) एस. सी. 1962 का उल्लेख किया गया है।

1.4 . केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, हालाँकि उन सभी के खिलाफ

साक्ष्य, जहाँ तक प्रत्यक्ष गवाही की बात है, एक ही परिणाम के रूप में आवश्यक नहीं है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है उन्हें भी बरी कर दिया जाना चाहिए। यह हमेशा एक अदालत के लिए खुला है बरी किए गए अभियुक्तों को उन अभियुक्तों से अलग करें जो दोषी ठहराए गए।[193

एफ] गुरुचरण सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 460, पर भरोसा व्यक्त किया |

1.5 . सामान्य विसंगतियाँ किसी पार्टी की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं। मामले में, भौतिक विसंगतियां ऐसा करती हैं। तत्काल मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित न्यायालयों ने जहाँ तक बरी किए गए और दोषी ठहराए गए अभियुक्तों का संबंध है, साक्ष्य में विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। [194 - ई]

1.6 . संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिरंजित समर्पण नहीं होना चाहिए काल्पनिक शंकाओं या लंबे समय से चले आ रहे संदेह को पोषित करना और इस तरह सामाजिक रूप से नष्ट करना।

रक्षा। न्याय को इस दलील पर निष्फल नहीं बनाया जा सकता है कि एक निर्दोष को दंडित करने की तुलना में सौ दोषियों को भागने देना बेहतर है। दोषियों को भागने देना कानून के अनुसार न्याय करना नहीं है। [194 - जी]

शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1974] 1 एससीआर 489

और यू. पी. राज्य बनाम कृष्ण गोपाल, ए. आई. आर. 2988 एस. सी. 2154 पर भरोसा किया।

गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह और अन्य। , आकाशवाणी (1990) एससी 209; राज्य

यू. पी. वी. अशोक कुमार श्रीवास्तव, आकाशवाणी (1992) एससी 840; इंदर सिंह और अन्न। वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन), आकाशवाणी (1978) अनुसूचित जाति 1091 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। अनिल सिंह, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 1998 ने इसका उल्लेख किया।

2.1 . गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व को प्रेरित नहीं कर सकती है, जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो और वह उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक हो। जहाँ गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। [197 - एच;

198-ए]

2.2 . यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक एक व्यक्ति के खिलाफ एक स्पष्ट कार्य साबित होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि सभा गैरकानूनी थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। 'ऑब्जेक्ट' शब्द का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और इसे सामान्य बनाने के लिए, इसे 'सभी' द्वारा साझा किया जाना चाहिए! [198 - बी-सी]

2.3 : एक ही उद्देश्य एक व्यक्त समझौते द्वारा बनाई जा सकती है आपसी परामर्श के द्वारा , लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी अवस्था मे किया जा सकता किसी भी स्तर पर गैरकानूनी सभा के सभी या कुछ सदस्य और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या परिवर्तित या त्याग दिया जा सकता है। हालाँकि उन परिस्थितियों में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिन परिस्थितियों से सामान्य उद्देश्य को बुलाया जा सकता है, यह उचित रूप से हो सकता है सभा की प्रकृति से एकत्र किए गए हथियार और घटना स्थल पर या उससे पहले या बाद में व्यवहार। [197 - डी-ई; 199-ई।]

3.1 . धारा 149 के दो भागों के बीच के अंतर को नजरंदाज या मिटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित किया जाना एक मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के भीतर आता है या यह एक अपराध जैसे कि सभा के सदस्यों को पता था कि होने की संभावना है सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध और दूसरे भाग के भीतर आता है| हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जो सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध पहले भाग के भीतर होंगे, आम तौर पर, यदि हमेशा, दूसरे भाग के साथ, अर्थात्, ऐसे अपराध जिन्हें संभवतः सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया। तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों में, चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य पर्याप्त है आई. पी. सी. की धारा 149 को लागू करके अपराध को निश्चित करें। [200 - ए-बी-सी; 201-डी]

मसल्ली और अन्य बनाम . यू. पी राज्य . ए,आई ।आर (1965) एस. सी. 202; लालजी बनाम यू पी राज्य, [1989]। एस. सी. सी. 437 और उत्तर प्रदेश राज्य वी. दान सिंह और अन्य , (1997) 3 एस°स°सी 747 पर निर्भरता की गयी |

कामाक्षा राय और अन्यः बनाम यू॰पी॰ ए *आई*आर (2000) एस *सी* मे अंतर किया गया

पद्मसुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य. जे. टी. (2002) 3 एस. सी. निर्दिष्ट किया गया 1

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार ; आपराधिक अपील सं*-1282/2001

[कटक उच्च न्यायालय के दिनांक 16.7.1999 निर्णय और आदेश जो क्री॰अ॰सं -133/1990 मे पारित की गयी थी ,से उत्त्पन्न]

देबाशीष मिश्रा एवं शिबाशीष मिश्रा,-- अपीलकर्ता के लिए 1

जनार्दन दास, जी °बिसवाल और एस. मिश्रा—उत्तरदाताओं के लिए1

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था;-

अरिजीत पसायत, जे. यह अभियुक्त अपीलर्थी की दूसरी यात्रा है इस न्यायालय का अपनी दोषसिद्धि के आधार पर दी गयी सजा के विरुद्ध दंडनीय अपराध धारा 302 सहपठित पठित धारा 149 और धारा 148 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत ।

प्रथम अवसर पर उपरोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि के अलावा, अपीलार्थियों को धारा 307 के साथ धारा 149 आई°पी°सी के तहत भी दोषी ठहराया गया था।. हालाँकि, दूसरी घटना में, उक्त दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 324 के साथ धारा 149 के तहत एक में बदल दिया गया है।

संक्षेप मे इस मुकदमे मे अभियोजन पक्ष का कथन निम्न लिखित रूप से है ;--

31.12.1988 पर, जयराम दास और सदानन्द दास (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित) के बीच झगड़ा हुआ था और दूसरी ओर जगबंधु सामल (डी. डब्ल्यू. 1) मोटो हाट के पासबाजार क्षेत्र में एक शेड का व्यवसाय/निर्माण। जब जगबंधु अचानक उठे तो उनके सिर पर छप्पर में निकले एक बांस से टकरा गया और उन्हें कुछ चोट लगी। इसके बाद जब जयराम दास (पीडब्लू-1), गगन दास (पीडब्लू-5) और मृतक बलभद्रपुर ससान के पास अपने गांव की ओर बढ़े , उन्होंने देखा कि लाठी, तंबू आदि से लैस आरोपी व्यक्ति आ रहे थे। भयभीत होकर मृतक और उसके साथी गाँव की ओर भागे। गगन दास (पी. डब्ल्यू. 5) शिखर बल के घर के अंदर गए, जबकि अन्य तीन ने खुद को नीलकंठ रथ (पी. डब्ल्यू. 8) के घर के अंदर छिपा लिया। घर अभियुक्त व्यक्तियों से घिरा हुआ था जिन्होंने घर के दरवाजे और दीवारों पर वार किया और उनमें से कुछ

घर के अंदर घुस गए। अभियुक्त पंचानन (वर्तमान अपील में अपीलार्थी 10) और सुभाष सामल (वर्तमान अपील में अपीलार्थी 7) ने तीनों व्यक्तियों को घसीटा और उन पर हमला किया। उस समय, अभियुक्तों में से एक व्यक्ति चिल्लाया कि पुलिस कर्मी वे आ रहे थे और बाद में सभी आरोपी भाग गए। पीडब्लू-5, जिसने घटना को शिखर बल के घर के दरवाजे में एक छेद के माध्यम से देखा, ने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया। घटना में घायल हुए पीडब्लू-1 और सूचना देने वाले पीडब्लू-5 के अलावा, पीडब्लूएस सहित कुछ अन्य व्यक्तियों ने इस घटना को देखा था। 2 , 3 , 4 , 7 और 8. अंतिम दो गवाह उस घर के मालिक हैं जिसमें मृतक और उसके साथियों ने शरण ली थी और घटना के बारे में भी बात की थी, लेकिन कुछ को छोड़कर वे अन्य आरोपी व्यक्तियों का नाम नहीं ले पाए। जाँच की गई और उसके पूरा होने पर, आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया गया।

अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना का एक अलग संस्करण दिया।

उनके लिए, यह आरोप कि आरोपी व्यक्तियों ने सशस्त्र होने के कारण मृतक और उसके साथियों का बलभद्रपुर शासन तक पीछा किया, गलत है। वास्तव में, मोटो हैट में ही कुछ घटना हुई थी जहाँ डी. डब्ल्यू.-1 पर हमला किया गया था और खुद को बचाने के लिए उसने 'बहुंगा' लहराया था। नतीजतन, मृतक पीडब्लू-आई और सनातन घायल हो गए। अपनी दलील को साबित करने के लिए उन्होंने डी. डब्ल्यू.-1 और नौ अन्य लोगों से पूछताछ की। यह संकेत दिया गया था कि अपीलकर्ता-सुभाष सामल डी. डब्ल्यू.-1 का पुत्र है। उनके द्वारा यह दावा किया गया था कि चूंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के थे और मृतक कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए उन्हे गलत तरीके से फंसाया गया। मूल रूप से, 21 आरोपी व्यक्ति थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भद्रक ने उनमें से छह को बरी कर दिया और अन्य 15 को धारा 305 के तहत दोषी ठहराया। आई. पी. सी. की धारा 149 और आई. पी. सी. की धारा 148 के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के तहत और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

धारा 148 और आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के तहत दंडनीय। सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

जिन 15 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था, उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। एक खंड पीठ ने अपने दिनांकित निर्णय द्वारा 18.4.1995 अपील अर्थात् आपराधिक अपील

No.133/90 को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाली अपील किया गया था विशेष अनुमति याचिका No.4170/1995 से बाहर। इस न्यायालय ने देखा कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण किए बिना भी बहुत ही अनौपचारिक तरीके से अपील का निपटारा किया था और विवेक का कोई उचित उपयोग नहीं था। इसलिए, मामला वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया गया था। इस तरह उच्च न्यायालय ने अपील पर फिर से सुनवाई की और विवादित फैसले से 10 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और बाकी अभियुक्तों को बरी कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृष्ण मोहंती (अभियुक्त No.17) के संबंध में उच्च न्यायालय ने देखा कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी या अन्यथा पाए जाने का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था, और इसलिए, यह देखा गया कि यह माना जाना चाहिए कि उक्त कृष्ण मोहंती को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। द्वारा उच्च न्यायालय इसके विवादित निर्णय ने विशेष रूप से चार अभियुक्त व्यक्तियों यानी उसके समक्ष अपीलार्थी 1,2,3 और 15 को बरी करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय का दिनांकित 16.7.1999 का निर्णय इस अपील में चुनौती का विषय है। अभियुक्त अपीलार्थी सं. 7, सुभाष सामल के आत्मसमर्पण न करने के कारण विशेष अनुमति याचिका के स्तर पर, याचिका को दिनांक 18/7/2000 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। , जहाँ तक उसका संबंध है कि हालांकि अपने पिछले फैसले से इस न्यायालय को उच्च न्यायालय की आवश्यकता थी प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य का विश्लेषण करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। वास्तव में, जैसा कि पहले किया गया था, उच्च न्यायालय सामान्यीकृत आधार पर आगे बढ़ा है। मुख्य नेत्र गवाह पीडब्लू हैं। 1 और 5 मृतक के रिश्तेदार हैं और दूसरे चश्मदीद गवाह उसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिससे मृतक और पीडब्लू -1 और 5 थे। गवाहों ने विशेष रूप से नहीं कहा है,किसी अभियुक्त व्यक्तियों को किसी भी निश्चित भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया। वास्तव में उन्होंने सर्वव्यापी तरीके से कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने हमला किया था। यह असंभव है कि पीडब्लू-5 घटना को एक छोटे से छेद के माध्यम से देख सकता था, जैसा कि उसने दावा किया था। निचली अदालत द्वारा बरी किए गए चार अभियुक्त समान आधार पर खड़े थे और उनके बरी होने का तर्क वर्तमान अपीलार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिखर बल जिनके घर में पीडब्लू 5 ने दावा किया था शरण लेने के लिए, जांच नहीं की गई है और पीडब्लू। 7 और 8 जो स्वतंत्र गवाह हैं, उन्होंने भी सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान नहीं की है और उनमें से केवल कुछ की ही पहचान की है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सनातन कौन था घायल की भी जांच नहीं की गई है। यदि अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार किया जाना है, तो ओवरट एक्ट का आरोप आरोपी कटिया, सुभाष सामल, हेमंत नायक और पंचानन बल (क्रमशः 4,7,8 और 10) को लगाया गया है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि दूसरों को दोषी क्यों ठहराया जाना चाहिए था। धारा 149 के तत्व मौजूद नहीं हैं क्योंकि

गवाहों ने अभियुक्त द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं, यदि कोई हो, के बारे में नहीं कहा है और केवल सर्वव्यापी बयान धारा 149 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्षा संस्करण अधिक संभावित है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। एक विसंगति थी तथाकथित चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य और अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य के बीच। बोलिनेदी वेंकटरमैया और ओआरएस के संदर्भ में। वी. आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1994) एस. सी. 76 में कहा गया है कि धारा 149 के आवेदन से पहले इच्छुक गवाहों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और विद्वान वकील के अनुसार वर्तमान मामले में उक्त कार्य नहीं किया गया है। कामाक्षा राय और अन्य बनाम यू. पी. राज्य , ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 53 के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 149 को लागू करने के लिए सर्वव्यापी कथन पर्याप्त नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को या तो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और तथाकथित आंख के साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है एक ही गवाहों, एक अलग मापदंड इस हद तक लागू नहीं किया जाना चाहिए था जो याचिकाकर्ता से संबंधित हैं।

प्रतिउत्तर के जवाब में, राज्य के विद्वान वकील श्री जे. आर. दास ने बहस किया कि

चश्मदीद गवाहों की गवाही स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय होती है। केवल इसलिए कि वे एक विशेष राजनीतिक दल से संबंधित थे, इस बात का कोई कारण नहीं है कि वे क्यों अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया जाएगा। उन्हें गलत तरीके से फंसाने का कोई आधार स्थापित नहीं किया गया है। सभी अभियुक्तों को नामजद किया गया है। यह स्पष्ट रूप से सबूत पर लाया गया है कि वे मृतक और घायल गवाहों का पीछा करते हुए सशस्त्र थे और उन्हें बाहर लाने के लिए चिल्ला रहे थे जब उन्होंने शिखर बल के घर में शरण ली थी। केवल इसलिए कि शिखर बल से पूछताछ नहीं की गई है, यह किसी भी तरह से चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को कमजोर नहीं करता है। इसके अलावा, सनातन की गैर-परीक्षा से बहुत कुछ निकला है। यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि उसके ठिकाने का पता नहीं है और इसलिए उसकी जांच नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, पीडब्लू 7 ने यह नहीं कहा है कि दो अभियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर, जिनके नाम उसने लिए थे और जिनकी पहचान की थी, अन्य उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अन्य लोग वहाँ नहीं थे, और केवल यह कहा कि वह दो व्यक्तियों के नाम जानते थे। साझा इरादा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, यह चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को संदिग्ध नहीं बनाता है। दो अदालतों ने स्पष्ट रूप से पाया है कि आरोपी व्यक्ति मृतक और अन्य लोगों का पीछा करते हुए सशस्त्र थे, उस घर में घुस गए जहां वे शरण ले रहे थे और उन्हें बाहर ले आए, और इस घटना में एक गवाह घायल हो गया था, जबकि मृतक की जान चली गई थी। तथ्य के ये

निष्कर्ष प्रकृति में निर्णायक हैं और इसके लिए हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

हम सबसे पहले अभियोजन पक्ष के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रुचि के बारे में विवाद पर विचार करेंगे। संबंध एक कारक नहीं है जो गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। यदि गलत निहितार्थ का अनुरोध किया जाता है तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में,न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। दलीप सिंह और अन्य बनाम. पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1953) एस. सी. 364 मे निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं आता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ शत्रुता जैसे कारण नहीं हैं, कि वह उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है। आम तौर पर एक करीबी संबंध होगा वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए अंतिम। यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ एक गवाह को दोषी के साथ दुर्भावना होती है, लेकिन इस तरह की आलोचना और केवल तथ्य के लिए नींव रखी जानी चाहिए एक नींव होने से दूर संबंध अक्सर एक सच की निश्चित गारंटी है 1

हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए किए जाते हैं जो अक्सर हमारे सामने मामलों में सामने रखी जाती हैं। विवेक का सामान्य नियम। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले में इसे अपने तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्णय के बाद से गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [1974] 3 एस. सी. सी. 698 मे इसका पालन किया गया है , जिसमें वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. (1957) एस. सी. 614 पर भी भरोसा किया गया था।

हम यह भी देख सकते हैं कि गवाह के करीब होने का आधार रिश्तेदार और परिणामस्वरूप एक

पक्षपाती गवाह होने पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई सार नहीं है। इस सिद्धांत को इस अदालत ने दलीप सिंह के मामले (ऊपर) में ही खारिज कर दिया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। विवियन बोस, जे. के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गयाः " हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता है। अगर इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएँ हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर टिका हुआ है, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक से निकट संबंध रखते हैं तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं।

यह कई आपराधिक मामलों में एक आम भ्रांति है और जो इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 'रामेश्वर बनाम' राजस्थान राज्य आकाशवाणी (1952) एससी 54 पी। 59 मे मामले को खारिज करने का प्रयास किया गया . हालाँकि, हम पाते हैं कि यह दुर्भाग्य से अभी भी, यदि न्यायालयों के निर्णयों में नहीं है, तो किसी भी तरह से वकील की दलीलों में बना हुआ है। फिर से मसाला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी (1965) एससी 202 मे यह न्यायालय ने टिप्पणी कीः (पी, 209-210 पैरा 14):

" लेकिन हम समझते हैं कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि

पक्षपाती या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य एकमात्र इस आधार पर कि यह पक्षपातपूर्ण है, ऐसे साक्ष्य की अस्वीकृति हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगी। कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं रखा जा सकता है। कितने सबूतों की सराहना की जानी चाहिए। इस तरह के साक्ष्य से निपटने में न्यायिक दृष्टिकोण से सतर्क रहना होगा; लेकिन . याचिका कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण नहीं हैसही के रूप में स्वीकार किया जाए।

पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, आकाशवाणी (1973) एससी 2407 और लेहना बनाम। हरियाणा राज्य, [2002] 3 एससीसी 76। मे बनी इसी प्रभाव का निर्णय लिया गया है1 अभियुक्त-अपीलार्थियोंद्वारा पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने की वांछनीयता के बारे में तर्क देने के लिए कुछ गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अस्वीकृति पर जोर दिया गया था। सार में प्रार्थना में "फाल्सस इन यूनो फाल्सस" के सिद्धांत को लागू करना है। सर्वव्यापी "(एक चीज में गलत, हर चीज में गलत)। यह दलील स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।

यदि साक्ष्य के बड़े हिस्से में कमी पाई जाती है, तो भी यदि किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अवशेष पर्याप्त हैं, तो कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बरी किए जाने के बावजूद, उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। भूसी से अनाज को अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहाँ भूसी को अनाज से अलग किया जा सकता है, वहाँ इस तथ्य के बावजूद कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य की कमी पाई गई है, किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय खुला रहेगा। विशेष भौतिक गवाह या विशेष रूप से सामग्री की असत शुरू से अंत तक इसे बर्बाद नहीं करेंगे। "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" उक्ति का भारत में कोई उपयोग नहीं है और गवाहों को झूठा नहीं माना जा सकता है। उक्ति "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है और न ही यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आई है।

यह केवल सावधानी का नियम है। यह केवल इतना है कि ऐसे मामलों में गवाही की अवहेलना की जा सकती है, न कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए। इस सिद्धांत में केवल साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे एक न्यायालय परिस्थितियों के एक दिए गए समूह में लागू कर सकता है, लेकिन यह वह नहीं है जिसे 'साक्ष्य का अनिवार्य नियम' कहा जा सकता है। निसार अल्ली बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1957) एस. सी. 366। केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है, हालाँकि उन सभी के खिलाफ साक्ष्य, जहाँ तक प्रत्यक्ष गवाही की बात है, एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं जाता है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है उन्हें भी बरी कर दिया जाना चाहिए। यह हमेशा एक अदालत के लिए खुला है बरी किए गए अभियुक्तों को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों से अलग करें। गुरुचरण सिंह और अन्न को देखें। वी. पंजाब राज्य, ए. आई. आर (1956) एस. सी. 460। यह सिद्धांत विशेष रूप से भारत में एक खतरनाक है अगर पूरे शरीर के लिए गवाही को अस्वीकार कर दिया जाना था, क्योंकि गवाह स्पष्ट रूप से किसी न किसी पहलू में झूठ बोल रहा था, इस बात की आशंका है कि आपराधिक न्याय का प्रशासन बंद हो जाएगा। गवाह एक कहानी को कढ़ाई देने में मदद नहीं कर सकते हैं, हालांकि, मुख्य रूप से सच है। इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकृति के योग्य है, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में न्यायालय इसे गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानता है, यह नहीं है अनिवार्य रूप से कानून के मामले के रूप में पालन करें कि इसे सभी मामलों में समर्थन की अवहेलना की जानी चाहिए।

साथ ही। साक्ष्य को सावधानी के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उपरोक्त उक्ति इस कारण से एक ठोस नियम नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में झूठ का एक दाना या किसी भी

तरह से अतिशयोक्ति न हो। कढ़ाई या अलंकरण। (सोहराब एस/ओ बेली नायता और अन्न को देखें। वी. मध्य प्रदेश राज्य, [1972] 3 एस. सी. सी. 751 और उगार अहिर और अन्य। वी. बिहार राज्य, आकाशवाणी (1965) एससी 277। एक प्रयास किया जाना चाहिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है ऊपर, सम्मानित रूपक के संदर्भ में, भूसे से अनाज, झूठ से सत्य को अलग करें। जहाँ सत्य को असत्य से अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि अनाज और भूसी अटूट रूप से मिश्रित हैं, और इस प्रक्रिया में

अलगाव एक बिल्कुल नए मामले को अनिवार्य रूप से तलाक देकर फिर से बनाना होगा। अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से प्रस्तुत किए गए विवरण, जिसके खिलाफ वे बनाए गए हैं, एकमात्र उपलब्ध तरीका है कि साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाए। ज़िंगली एरियल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए°आई°आर (1954) एससी 15 और बलाका सिंह और अन्य। बनाम पंजाब. राज्य ए॰आई॰आर (1975) एससी 1962। जैसाकि एहि न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम में अभिनिर्धारित कयल गेल अछि। श्रीमती. कल्कि और अन्न। , ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 1390, साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों के कारण होती हैं। समय के अंतराल के कारण स्मृति, मानसिक स्वभाव के कारण जैसे सदमे और घटना के समय भय और वे हमेशा वहाँ होते हैं, चाहे कोई ईमानदार और सच्चा गवाह क्यों न हो। भौतिक विसंगतियाँ वे हैं जो नहीं हैं सामान्य, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, भौतिक विसंगतियाँ ऐसा करती हैं। इन पहलुओं पर हाल ही में कृष्ण मोची और अन्य बनाम बिहार. राज्य आदि, जे. टी. [2002] 4 एस. सी. 186। अभियुक्त-मामले में अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित न्यायालयों ने जहाँ तक बरी किए गए और दोषी ठहराए गए अभियुक्तों का संबंध है, साक्ष्य में विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह अभियुक्त के बरी होने के कारण संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि साक्ष्य अपराध को मजबूत करने के लिए अपर्याप्त है, और इसलिए अभियोजन पक्ष को संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिरंजित समर्पण को काल्पनिक संदेह या लंबे समय तक संदेह को पोषित नहीं करना चाहिए और इस तरह सामाजिक सुरक्षा को नष्ट नहीं करना चाहिए। न्याय को इस दलील पर निष्फल नहीं बनाया जा सकता है कि एक निर्दोष को दंडित करने की तुलना में सौ दोषियों को भागने देना बेहतर है। दोषियों को भागने देना न्याय करना नहीं है। कानून के अनुसार। देखिएः गुरबचन सिंह बनाम। सतपाल सिंह और अन्य। ,

ए°आई°आर (1990) एससी 209। किसी भी और प्रत्येक परिकल्पना को पूरा करने के लिए अभियोजन की आवश्यकता नहीं है अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया। यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, ए°आई°आर (1992) एससी 840 एक उचित संदेह एक काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है। यह मामले में साक्ष्य से विकसित होना चाहिए। यदि कोई मामला पूरी तरह से साबित हो जाता है, तो यह तर्क दिया जाता है कि यह कृत्रिम है; यदि किसी मामले में कुछ खामियां अपरिहार्य हैं क्योंकि मनुष्य गलतियों के लिए प्रवण हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि यह बहुत अपूर्ण है। एक आश्चर्य।

चाहे एक दुर्लभ निर्दोष को दंडित होने से समाप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक अतिसंवेदनशीलता में, कई दोषी व्यक्तियों को भागने की अनुमति दी जानी चाहिए। सबूत से परे उचित संदेह एक दिशानिर्देश है, बुतपरस्ती नहीं। इंदर सिंह और अन्न को देखें। वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन), आकाशवाणी (1978) एससी 1091। न्यायिक मूल्यांकन की अस्पष्ट खोज नहीं हो सकती है। एक न्यायाधीश आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता केवल यह देखने के लिए नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए। दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (स्टर्लैंड बनाम में प्रति विस्काउंट साइमन। लोक अभियोजन निदेशक, (1944) ए. सी. (पी. सी.) 325)

यू. पी. राज्य बनाम अनिल सिंह, आकाशवाणी (1988) एससी 1998। संदेह को उचित कहा जाएगा यदि वे अमूर्त अटकलों के उत्साह से मुक्त हैं। कानून सच्चाई के अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता है।

इस तरह के मामलों में, शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों को याद करना उचित है। महाराष्ट्र राज्य, [1974] । एससीआर

489 (492-493)] :

..... सामाजिक रक्षा की कीमत पर संदेह के लाभ के नियम के प्रति अतिरंजित समर्पण के खतरे और इस सुखदायक भावना के लिए कि पीड़ित और समुदाय के लिए न्याय की परवाह किए बिना सभी दोषमुक्त हमेशा अच्छे होते हैं, अपराध और पलायन को बढ़ाने के समकालीन संदर्भ में विशेष जोर देने की मांग करते हैं। न्यायिक साधन में सार्वजनिक जवाबदेही होती है। उचित संदेह से परे सबूत के पोषित सिद्धांत या सुनहरे धागे, जो हमारे कानून के जाल से गुजरते हैं, को हर आशंका को गले लगाने के लिए विकृत रूप से नहीं फैलाया जाना चाहिए। हिचकिचाहट और संदेह की डिग्री "।

..... 'प्रूफ ऑफ गिल्ट' में एक विद्वान लेखक ग्लैनविल विलियम्स के रूप में एक दोषी व्यक्ति को हल्के-फुल्के दिल से बरी करने की बुराई ने समझदारी से काम लिया है। देखा गया, इस सरल तथ्य से बहुत आगे जाता है कि, केवल एक दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है। यदि बिना शर्त बरी किए जाने के मामले सामान्य हो जाते हैं, तो वे कानून की सनकी अवहेलना की ओर ले जाते हैं, और यह बदले में अभियुक्त 'व्यक्तियों' के खिलाफ कठोर कानूनी अनुमानों और दोषी पाए जाने वालों को अधिक कठोर सजा देने की सार्वजनिक मांग की ओर ले जाता है। इस प्रकार दोषियों को बार-बार बरी करने से एक क्रूर दंडात्मक कानून बन सकता है, जो अंततः न्यायिक संरक्षण को समाप्त कर सकता है। अपराधबोध '। ..... न्याय का गर्भपात बरी होने से उत्पन्न हो सकता है

निर्दोष के दोषसिद्धि से कम नहीं। "यू. पी.राज्य बनाम राज्यए. गोपाल, आकाशवाणी (1988) एससी 2154 मे इसे फिर से प्रकाश मे लाया गया इस मोड़ पर, इस दलील पर विचार करना उचित होगा कि साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य भिन्न हैं। यह गलत होगा।नेत्र-गवाहों के खाते के लिए चिकित्सा गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना, जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना था और चिकित्सा साक्ष्य को "स्थिर" रखते हुए "चर" के रूप में प्रस्तुत किया जाना था। कृष्ण गोपाल का मामला (ऊपर), स्थिति को संक्षिप्त रूप से बताया गया है

ओडब्ल्यूएसः " यह सामान्य बात है कि जहां चश्मदीद गवाहों का विवरण विश्वसनीय पाया जाता है और विश्वसनीय, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। गवाह, जैसा कि बंथम ने कहा, हैं न्याय की आँखें और कान। इसलिए इसका महत्व और प्रधानता परीक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता। चश्मदीद गवाहों के खाते की आवश्यकता होगी उनकी विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक स्वतंत्र मूल्यांकन और मूल्यांकन

जिसे किसी अन्य साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल रूप से पूर्वाग्रही नहीं माना जाना चाहिए, चिकित्सा साक्ष्य सहित, इस तरह के परीक्षण के लिए एकमात्र टचस्टोन के रूप में विश्वसनीयता। साक्ष्य की अंतर्निहित स्थिरता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। और कहानी की अंतर्निहित संभावना; अन्य गवाहों के खाते के साथ निरंतरता को श्रेय-योग्य माना जाता है; निर्विवाद तथ्य गवाहों का 'श्रेय' है; गवाह-पेटी में उनका प्रदर्शन; उनकी अवलोकन की शक्ति आदि। तब ऐसे साक्ष्य का संभाव्य मूल्य इसके लिए पैमाने में रखे जाने के योग्य हो जाता है एक संचयी मूल्यांकन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराए जाने का गहरा अधिकार है। एक अपराध जो साक्ष्य मानक द्वारा स्थापित नहीं है उचित संदेह से परे सबूत।

हालांकि यह मानक एक उच्च है

मानक, हालांकि, कोई पूर्ण मानक नहीं है। किस डिग्री का? 'प्रमाण' विशेष रूप से प्रत्येक के लिए एक अभ्यास है मामला। 'प्रमाण' के लिए संभावना राशि का उल्लेख करना एक अभ्यास हैसाक्ष्य की अंतर-निर्भरता और एक टुकड़े की पुष्टि एक अन्य विद्वान लेखक का साक्ष्य कहता हैः ("द मैथेमैटिक्स ऑफ सबूत ॥ ": ग्लेनविल विलियम्सः स्वीट द्वारा आपराधिक कानून समीक्षा, 1979 और मैक्सवेल, पी। 340 (342) . संदेह को उचित कहा जाएगा यदि वे अमूर्त अटकलों के उत्साह से मुक्त हैं। कानून सच्चाई के अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता है। उचित संदेह का गठन करने के लिए, यह एक अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिए। केवल अस्पष्ट आशंकाओं के विपरीत, साक्ष्य से या इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले अभियुक्त व्यक्ति के अपराध के बारे में संदेह वास्तविक और पर्याप्त संदेह होने चाहिए। एक उचित संदेह एक काल्पनिक, तुच्छ या केवल एक संभावित संदेह नहीं है; बल्कि कारण और सामान्य समझ पर आधारित एक उचित संदेह है। यह सबूतों से विकसित होना चाहिए। मामले मे संभाव्यता की अवधारणाओं और इसकी डिग्री को स्पष्ट रूप से गणितीय रूप से गणना की जाने वाली इकाइयों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ऐसी कितनी इकाइयाँ उचित संदेह से परे प्रमाण का गठन करती हैं। संभाव्यता की डिग्री और प्रमाण की मात्रा के मूल्यांकन में एक अचूक व्यक्तिपरक तत्व है। फोरेंसिक संभाव्यता अंतिम विश्लेषण में, एक मजबूत सामान्य ज्ञान और अंततः न्यायाधीश के प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान पर निर्भर होना चाहिए। जबकि द्वारा दी गई सुरक्षा अभियुक्त व्यक्तियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया को नष्ट नहीं किया जाना है, उसी समय, तुच्छताओं का अनजान वैधता एक

आपराधिक न्याय के प्रशासन का उपहास "।एक अन्य याचिका जिस पर जोर दिया गया था, वह इस सवाल से संबंधित है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 149 में रचनात्मक दायित्व को निर्धारित करने के लिए कोई आवेदन है जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य है। आम मंशा पर नहीं बल्कि आम मंशा पर जोर दिया जाता है। केवल एक गैरकानूनी सभा में उपस्थिति। अधिक व्यक्ति और क्या उक्त व्यक्ति धारा 141 में निर्दिष्ट सामान्य वस्तुओं में से एक या अधिक का मनोरंजन करते हैं। यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एक स्पष्ट कार्य साबित नहीं होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए था कि सभा गैरकानूनी थी और इसके करने की संभावना थी

कोई भी कार्य जो धारा 141 के दायरे में आता है। 'ऑब्जेक्ट' शब्द का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए, इसे सभी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वस्तु के लिए सामान्य होना चाहिए व्यक्ति, जो सभा की रचना करते हैं, अर्थात, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इसमें सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते से एक सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। यह हो सकता है गैर कानूनी सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किसी भी स्तर पर गठित किया गया और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या परिवर्तित या त्याग दिया जा सकता है। धारा 149 में दिखाई देने वाली 'सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में' अभिव्यक्ति को 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के बराबर के रूप में सख्ती से समझा जाना चाहिए। इसे वस्तु की प्रकृति के आधार पर तुरंत सामान्य वस्तु से जोड़ा जाना चाहिए। वस्तु का समुदाय होना चाहिए और वस्तु केवल एक विशेष चरण तक मौजूद हो सकती है, और उसके बाद नहीं। गैरकानूनी सभा के सदस्य में कुछ बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है, जिसके परे वे अपने उद्देश्यों में भिन्न हो सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में ज्ञान न केवल उसके आदेश पर जानकारी के अनुसार भिन्न हो सकता है, बल्कि उस सीमा के अनुसार भी हो सकता है जिस तक वह उद्देश्य के समुदाय को साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर आई. पी. सी. की धारा 149 का प्रभाव भिन्न हो सकता है।

' 'सामान्य उद्देश्य' एक 'सामान्य इरादे' से अलग है क्योंकि इसमें हमले से पहले एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की एक सामान्य बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह. यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु है और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं। एक सभा के 'सामान्य उद्देश्य' का निर्धारण इसे बनाने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से और आसपास के सभी पहलुओं पर विचार करके किया जाना है। परिस्थितियाँ। इसे अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है। सभा के सदस्य। घटना के एक विशेष चरण में गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके पास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सभी मामलों में, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, इसे कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए या सफल होना चाहिए। धारा 141 के

स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा जो इकट्ठा होने के समय गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सभा को गैरकानूनी बनाने के लिए आवश्यक इरादा या उद्देश्य शुरू में ही अस्तित्व में आ जाए। गैरकानूनी इरादे बनाने का समय भौतिक नहीं है। एक सभा जिसमें प्रारम्भ या उसके बाद कुछ समय के लिए भी वैध है, जो बाद में गैरकानूनी हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह घटना के दौरान मौके पर तुरंत विकसित हो सकता है। आई. पी. सी. की धारा 149 के दो भाग हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाने वाला अपराध वह होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। ताकि अपराध पहले भाग के भीतर आ सके, अपराध को तुरंत गैरकानूनी के सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। सभा जिसका अभियुक्त सदस्य था। भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अभियोजन में नहीं है, फिर भी यह धारा 141 के तहत आ सकता है, अगर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसा कि सदस्यों को पता था कि किए जाने की संभावना थी और यही धारा के दूसरे भाग में अपेक्षित है। जिस उद्देश्य के लिए सभा के सदस्य निर्धारित करते हैं या जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वह उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य समान है, तो जिस ज्ञान का अनुसरण किया जा रहा है, वह सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे सामान्य रूप से इस बात पर सहमत होते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाना है और अब यह सभा का सामान्य उद्देश्य है। मानव मस्तिष्क में वस्तु का मनोरंजन किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण होने के कारण, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है और इरादे की तरह, आम तौर पर उस कार्य से एकत्र किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है और उसका परिणाम होता है। हालाँकि परिस्थितियों के तहत कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसे सामान्य वस्तु कहा जा सकता है, इसे उचित रूप से सभा की प्रकृति, उसके द्वारा वहन किए जाने वाले हथियारों और घटना स्थल पर या उससे पहले या बाद में व्यवहार से एकत्र किया जा सकता है। खंड की दूसरी शाखा में प्रयुक्त 'ज्ञात' शब्द का अर्थ एक संभावना से अधिक कुछ है और इसे बनाया नहीं जा सकता है।

'ज्ञात हो सकता है' की भावना को सहन करने के लिए। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसे गैरकानूनी सभा के सदस्य जानते थे

ऐसे मामले हैं जो अभियोजन में किए गए पहले अपराधों के भीतर होंगे सामान्य उद्देश्य आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे के साथ होगा, अर्थात्, ऐसे अपराध जो पक्षकारों के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे। चिक्कारंगे गौड़ा और अन्य बनाम मैसूर राज्य, ए °आई °आर (1956) एससी 731

देखे

दूसरी दलील है कि निश्चित भूमिकाओं का श्रेय अभियुक्त को नहीं दिया गया है और इसलिए धारा 149 लागू नहीं है, असमर्थनीय है। मसाल्ती के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की 4-न्यायाधीश पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" फिर यह आग्रह किया जाता है कि गवाहों द्वारा दी गई गवाही एक समान पैटर्न के अनुरूप हो और क्योंकि कोई विशिष्ट भाग उन्हें नहीं सौंपा गया है। सभा, गवाहों के लिए अक्सर हमलावरों में से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना संभव नहीं होता है। इसके अलावा, यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ इच्छित पीड़ितों पर हमला करती है, तो यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि उन सभी को वास्तविक हमले में भाग लेना पड़े। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में गैरकानूनी सभा के विभिन्न सदस्यों द्वारा कई हथियार लिए गए थे, लेकिनऐसा प्रतीत होता है कि बंदूकों का इस्तेमाल किया गया और यह 5 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था। ऐसे मामले में; कि क्योंकि दूसरे मामले में, यह तर्क देना अनुचित होगा गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा ले जाए गए हथियार नहीं थे प्रयुक्त, उक्त हथियारों के संबंध में कहानी को ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। ऐसे जटिल मामले में साक्ष्य की सराहना करना निस्संदेह एक कठिन कार्य है, लेकिन आपराधिक अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और यह उनका कर्तव्य है कि वे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक छान-बीन करें और यह तय करें कि इसका कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा नहीं। लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1989] 1 एससीसी 437मे अवलोकन का भी ऐसा ही प्रभाव है 1 यह देखा गया कि -

" गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से एकत्र किया जा सकता ह सभा की प्रकृति, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भुजाएँ और उनके व्यवहार घटना स्थल पर या उससे पहले सभा।यएक अनुमान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाए।

यू. पी. राज्य बनाम दान सिंह और अन्य , [1997] 3 एससीसी 747 मे यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों में से किस ने कौन सा या क्या कार्य किया। संदर्भ था लालजी के मामले (ऊपर दिए गए) में कहा गया है कि जहां यह देखा गया था कि "प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति के सामान्य इरादे का संकेत दे सकती है, वहीं गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति परोक्ष रूप से हो सकती है। धारा 149 "के तहत आपराधिक दायित्व। स्थिति होने के ऊपर, हम याचिका में कोई सार नहीं पाते हैं कि सबूत धारा

149 को लागू करके दोषी ठहराए जाने के लिए चश्मदीद गवाहों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक कामाक्षा राय के मामले (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियों का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में निर्णय एक अलग तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था।

पूरी तरह से परिदृश्य किसी निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष अधिनियम के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं। परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है (पद्मसुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। , जे. टी. (2002) 3 एस. सी. 1. देखे यह एक ऐसे मामले में अधिक है जहां निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना से संबंधित है एक आपराधिक मुकदमा, जैसा कि कृष्ण मोची के मामले (ऊपर) में देखा गया था।

इस अपील का अपरिहार्य परिणाम बर्खास्तगी है जिसे हम निर्देशित करते हैं।

अपील याचिका खारिज कर दी गई।

.